

शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण के प्रभाव का औचित्य

सारांश

आज का युग निजीकरण का युग है और इस निजीकरण ने हमारी शिक्षा प्रणाली को भी अपने जाल में जकड़ रखा है। आज शिक्षा वह नींव है जिस पर आधुनिक समाज के स्तम्भ खड़े हैं हमारी सरकारें बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखने के लिए अनेकों प्रयत्न कर रही है। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा कानून लागू हो जाने के पश्चात् सरकार और सरकारी विद्यालयों की जिम्मेदारी बनती है कि वह देश के सभी बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराए। हमारी शिक्षा पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 2.8 प्रतिशत है जबकि विकसित देशों में शिक्षा पर व्यय 6 प्रतिशत या उससे भी अधिक है। सरकारी विद्यालयों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय भवन के अतिरिक्त अन्य संसाधनों का आभाव पाया जाता है। आज अन्य क्षेत्रों में निजीकरण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए यह माना जा रहा है कि इस प्रयोग से हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी अमूल परिवर्तन दिखायी देगा।



जगदम्बा सिंह

शोध छात्र,

शिक्षाशास्त्र विभाग,

मोहनलाल सुखाड़िया वि० विद्यालय,

उदयपुर

मुख्य शब्द : निजीकरण, शिक्षा, क्षेत्र, औचित्य

प्रस्तावना

निजीकरण का अर्थ है सरकार के नियंत्रण से बाहर रखकर कार्य करने की विधि यह व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकता है या सामूहिक स्तर पर निजीकरण एकाधिकार का प्रतीक होता है यद्यपि निजीकरण लाभकारी है तथापि अन्ततोगत्वा निजीकरण दुष्परिणाम ही देता है।

आज पूरी दुनिया में ज्ञान का विस्तार तेजी से हो रहा है। शिक्षा मानव संसाधन के विकास का आधार बन गयी है लेकिन यह एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या शिक्षा पाने के लिए बच्चों को सरकारी विद्यालय की शरण में जाना जरूरी है ? क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में यह ज्यादा अहमियत रखती है कि विद्यालय सरकारी हो या निजी।

सरकारी विद्यालयों की खस्ता हालत को देखते हुए अभिभावक अब अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजने के बजाय निजी विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं।

आज सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की स्थिति चरमरा गई है और लोग निजी संस्थाओं की ओर पलायन करने लगे हैं जैसे सभी को मालूम है कि सरकारी संस्थाओं में जो शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहे हैं वे निजी संस्थाओं की अपेक्षा ज्यादा योग्य और विज्ञ हैं लेकिन इन संस्थाओं में आधुनिक संसाधनों का आभाव है जिससे छात्र शिक्षकों का अधिक से अधिक दोहन नहीं कर पा रहे हैं। निजी शिक्षण संस्थाओं के बारे में यह कहावत चरितार्थ होती है "ऊँची दुकान फीका पकवान" निजी शिक्षण संस्थाओं की कोशिश होती है कि वे अपने शिक्षा रूपी व्यवसाय को आधुनिक साज सज्जा से संवारकर लोगों के बीच पेश करें क्योंकि आज का युग मार्केटिंग का युग है आप अपनी संस्था का प्रचार प्रसार कर उन्हें आकर्षक भवन, आकर्षक सुविधाओं, खेलकूद का मैदान, आधुनिक तकनीक द्वारा शिक्षण, आर० ओ० युक्त पीने का पानी आदि से अभिभावकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल होते हैं।

वर्तमान में लोगों के जेहन में अंग्रेजी भाषा के प्रति इतनी ललक देखी जा रही है उसी का लाभ उठाकर ये निजी संस्थाएँ अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई का शोषण कर रही हैं। निजी विद्यालय अपनी छद्म योजनाओं से प्रवेश को कठिन बनाकर मांग एवं पूर्ति का खेल खेलती हैं। सरकारी शिक्षण संस्थाएँ इन आकर्षणों से निजी संस्थाओं का मुकाबला नहीं कर पाती हैं इसलिए उनके प्रति लोगों में विशेष लगाव नहीं है। आज के समय में स्कूल कालेज आलीशान पांच सितारा में बदलते जा रहे हैं। शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है कहकर भी हकीकत में निजी स्कूल कालेज फलते फूलते जा रहे हैं इनकी संख्या में गुणात्मक वृद्धि हो रही है लेकिन इसमें गुणवत्ता का आभाव देखा जा रहा है। निजीकरण की नीति ने शिक्षा को एक माल या व्यवसाय के

रूप में तब्दील कर दिया है आज छोटे व्यापारी से लेकर बड़े-बड़े पूंजीपति मुनाफा कमाने की गरज से स्कूल कालेज खोलने लगे हैं और ये शिक्षण संस्थाएँ आज फ़ैक्ट्री का रूप लेती जा रही हैं।

निजीकरण के इस पूरे दौर की हकीकत यह है कि गुणवत्ता विहीन मंहगी शिक्षा ही उपलब्ध है। शिक्षा का सामाजिक महत्व खत्म हो गया है और निजी हित ऊपर हो गये हैं। निजीकरण के दौर में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र चला रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता का प्रलोभन देकर निजी हाथों को प्रोत्साहित किया गया।

निजीकरण के उद्देश्य

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हर क्षेत्र में निजीकरण का बढ़ता चलन और उससे हो रहे अनेको लाभों से शिक्षा के निजीकरण की तरफ सरकार और लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ जिसके परिणामस्वरूप शिक्षा के निजीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ी है छोटे छोटे कुकुरमुत्ते सरीखे स्कूल कालेज हमारे सामने हैं। शिक्षा को निजीकरण करने के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. शिक्षा को निजी हाथों में सौंपकर अधिक कार्य कुशलता और उत्पादकता को बढ़ाना।
2. शिक्षित और उद्यमशील युवाओं को अवसर प्रदान करके रोजगार में वृद्धि लाना।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की कार्यक्षमता में सुधार करना।
4. सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागेदारी से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
5. शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि लाना।
6. राष्ट्र के निर्माण के प्रति जवाबदेह बनाना।

शिक्षा के निजीकरण के कारण

आज के दौर में अंग्रेजी भाषा की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है और अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने हेतु निजी विद्यालयों का तरफ देख रहे हैं। अभिभावकों के अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजने के पीछे मुख्य कारण हैं।

1. जनसंख्या वृद्धि
2. सरकारी शिक्षा प्रणाली में खामियां
3. शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप
4. संसाधनों का आभाव
5. देश की जनता का सरकारी संस्थाओं के प्रति अविश्वास
6. अध्यापन कार्य में गुणवत्ता का आभाव
7. शिक्षकों का शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में इस्तेमाल।

निजीकरण का प्रभाव

निजी शिक्षण संस्थाओं में देखा जाय तो विशेष तौर पर समाज के धनाढ्य वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करना होता है दूसरी तरफ इनकी व्यक्तिगत सोच ने समाज के गरीब वर्ग के मन में हीन भावना को जन्म दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण के प्रभाव को निम्न रूप से देखा जा सकता है—

1. गुरु और शिष्य के रिश्ते पर हावी बाजार
2. दाखिले से वंचित होता गरीब तबका
3. बिना रोजगार पैदा किए उत्पादन में वृद्धि
4. स्तरविहीन डिग्री धारियों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि
5. पूंजीपतियों का शिक्षा रूपी फ़ैक्ट्री में निवेश की बढ़ती प्रवृत्ति।

निष्कर्ष

आजकल शिक्षा के क्षेत्र में निजी संस्थाओं का बोलबाला है पैसा फेंकिए और अपने बच्चों को जो चाहे बना दीजिए। महान व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन का मानना था कि मुझे कुछ बालक दे दो आप जो चाहो मैं उसे बना दूँ, ऐसा तभी संभव था जब बालक को उचित वातावरण दिया जाय लेकिन आज के दौर में पैसा फेंकिए और अपने बच्चों को जो चाहे बना दीजिए यही तो हो रहा है हर स्तर पर प्रतिभाओं का दोहन हो रहा है कही समर कैम्प के नाम पर तो कही कैम्पस सलेक्शन के नाम पर लूट है। इस भाग दौड़ की जिन्दगी में किसी को यह सोचने की फुर्सत नहीं है कि निजी शिक्षण संस्थाओं की फीस मंहगी है बच्चे इस माहौल में पढ़ेंगे तो वे खुद आगे चलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगे जाहिर है हम भ्रष्ट संस्कृति को जन्म दे रहे हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि आज हमारे सरकारी शिक्षण संस्थान यदि दिशाहीनता, नियोजनहीनता, पुरातन पाठ्यक्रम, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, वित्तीय संसाधनों के दुरुप्रयोग आदि समस्याओं से ग्रस्त हैं तो दूसरी तरफ निजी संस्थान फ़ैक्ट्रियों की भांति निवेश के बदले अधिक से अधिक धन की प्राप्ति व्यापार की भावना से संचालित हो रहे हैं। इस प्रकार के दोषों को दूर करके शिक्षा को सही दशा दिशा प्रदान की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डैंगेविरन (2006) गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में निजीकरण पर पुनर्चर्चा' अन्तर्राष्ट्रीय विकास का जर्नल खंड 18,469-488
2. भटनागर, सुरेश (2008) समकालीन भारत और शिक्षा, प्रकाशक आर०लाल० बुक डिपो। पेज सं०159-162
3. पाराशर, मधु (2010) समकालीन भारत और शिक्षा, प्रकाशक राधा प्रकाशन मंदिर, आगरा। पेज सं०235
4. विकीडिया ओ० आर० जी० डाट० काम।
5. एजूकेशन मिरर ओ० आर० जी० डाट० काम।